



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 486]
No. 486]

नई दिल्ली, रविवार, मई 14, 2006/वैशाख 24, 1928
NEW DELHI, SUNDAY, MAY 14, 2006/VAISAKHA 24, 1928

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2006

का.आ. 710(अ).—यतः लिबरेशन टाईगर ऑफ तमिल ईलम (जिसे इसके पश्चात् एलटीटीई कहा गया है) वास्तव में श्रीलंका स्थित एक संगठन है किन्तु इससे सहानुभूति रखने वाले इसके समर्थक तथा कार्यकर्ता भारत में फैले हुए हैं;

और यतः सभी तमिलों के लिए एक पृथक् राष्ट्र (तमिल ईलम) की स्थापना के एलटीटीई के लक्ष्य से भारत की संप्रभुता एवं भूभागीय अखण्डता को खतरा पैदा हो गया है, और भारतीय भू-भाग के एक हिस्से के भारत संघ से अंतरण या पृथक्कीकरण की स्थिति पैदा हो गई है, और इस प्रकार यह विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के दायरे में आता है;

और यतः प्रतिबंध के बावजूद लिट्टे समर्थकों द्वारा जुलूसों, प्रदर्शनों आदि के जरिए लिट्टे के लिए समर्थन जुटाने एवं इसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए श्रीलंका में जनभावनाओं का शोषण किया जा रहा है जिससे तमिलनाडु राज्य में अशांति और राज्य की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है;

और यतः अधिकांश आपराधिक मामलों, जिनमें एलटीटीई तथा तमिल नेशनल रिट्रिवल टूप्स (टीएनआरटी) तमिलनाडु लिबरेशन आर्मी (टीएनएलए) तथा तामिलियर पासाराई जैसे एलटीटीई गुट संलिप्त रहे हैं, में दोषसिद्धि हुई है परंतु तमिलनाडु में एलटीटीई समर्थक गुटों में तमिल ईलम की अवधारणा अभी भी एक लक्ष्य बनी हुई है। ये ताकतें अभी भी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सक्रिय हैं और इस प्रकार ऐसा संवेदनशील माहौल बना रही हैं जिसमें यदि लिट्टे को भारत में एक विधिसम्मत संगठन के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दे दी जाती है तो यह भारत की संप्रभुता और भूभागीय अखण्डता के लिए अत्यधिक हानिकार होगा।

और यतः लिट्टे श्रीलंका में निरंतर एक अत्यधिक शक्तिशाली, घातक और सुसंगठित आतंकवादी ताकत बना हुआ है और उसके तमिलनाडु एवं दक्षिण भारत के कुछ भागों में ठोस संबंध हैं। लिट्टे नशीले पदार्थों तथा पेट्रोल और डीजल जैसी आवश्यक वस्तुओं की श्रीलंका को तस्करी के लिए तमिलनाडु राज्य को आधार के रूप में लगातार इस्तेमाल करता आ रहा है।

और यतः लिट्टे तब तक एक शक्तिशाली आन्दोलन बना रहेगा और तमिलनाडु में लिट्टे के समर्थन आधार को बढ़ाने के लिए अलगाववादी भावनाएं भड़काता रहेगा जब तक श्रीलंका में जातीय शत्रुता जारी रहेगी और तमिल ईलम की मांग की जाती रहेगी, जिसे श्रीलंकाई तमिलों तथा श्रीलंका में भारतीय तमिलों के बीच भाषाई, सांस्कृतिक, जातीय और ऐतिहासिक घनिष्ठ साम्य होने के कारण तमिलनाडु में जबरदस्त समर्थन प्राप्त है।

और यतः उपरोक्त कारणों से केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि लिट्टे एक विधिविरुद्ध संगम है और ऐसी सभी अलगाववादी गतिविधियों को सभी संभव उपायों से नियंत्रित करने की निरंतर सख्त जरूरत है।

और यतः केन्द्रीय सरकार के पास सूचना है कि :—

- (i) हाल ही में तमिलनाडु राज्य में तलाशे गए लिट्टे काडरों, इसे छोड़ने वालों, इससे सहानुभूति रखने वालों की गतिविधियों की जांच से पता चला है कि तमिलनाडु में भेजे गए काडरों का अंततोगत्वा लिट्टे द्वारा विधिविरुद्ध कार्यकलापों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा;
- (ii) प्रतिबंध लागू होने के बावजूद भारत में लिट्टे समर्थक संगठनों और लोगों की गतिविधियां देखी गई हैं और इन ताकतों द्वारा लिट्टे को अपना समर्थन देने के प्रयास किए गए हैं;
- (iii) लिट्टे नेता अपने संगठन के बारे में भारत की नीति और अपनी गतिविधियों को रोकने के लिए राज्य तंत्र की कार्यवाही पर कड़ा रुख अपनाते रहे हैं;

और यतः, केन्द्र सरकार का यह मत है कि लिट्टे की उपरोक्त गतिविधियां भारत की सम्प्रभुता और भूभागीय अखण्डता के लिए और साथ ही लोक-व्यवस्था के लिए खतरा बनी हुई हैं और हानिकर हैं, इसलिए इसे विधिविरुद्ध संगम घोषित किया जाना चाहिए;

और यतः, केन्द्र सरकार का यह भी मत है कि (i) भारत की सम्प्रभुता एवं अखण्डता के लिए हानिकर इसकी सतत हिंसक एवं विध्वंसकारी गतिविधियों तथा (ii) इसके द्वारा लगातार सख्त भारत-विरोधी रुख अपनाए जाने और भारतीय राष्ट्रियों की सुरक्षा को संतत रूप से गंभीर खतरा पैदा किए जाने के कारण, लिट्टे को तत्काल प्रभाव से "विधिविरुद्ध संगम" घोषित करना आवश्यक है।

अतः, अब, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा लिब्रेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) को विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है और निदेश देती है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत किए जाने वाले किसी आदेश के अध्याधीन, सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. I-11034/1/2006-आई.एस. III]

एल. सी. गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2006

S.O. 710(E).—Whereas the Liberation Tigers of Tamil Eelam (hereinafter referred to as the LTTE), is an association actually based in Sri Lanka but having sympathizers, supporters and agents on the Indian soil;

And whereas the LTTE's objective for a separate homeland (Tamil Eelam) for all tamils threatens the sovereignty and territorial integrity of India, and amounts to cession and secession of a part of the territory of India from the Union and thus falls within the ambit of an unlawful activity;

And whereas, the turbulence in Sri Lanka is being exploited by pro-LTTE forces to draw up support for the LTTE and its cause by taking out processions, demonstrations, etc., in spite of the ban causing disquiet and threat to the security of the State of Tamil Nadu;

And whereas most of the criminal cases involving the LTTE and pro-LTTE groups like Tamil National Retrieval Troops (TNRT), Tamil Nadu Liberation Army (TNLA) and Tamiliar Pasarai, have ended in conviction but the Tamil Eelam concept still remains as a goal among the pro-LTTE groups in Tamil Nadu. The forces are still at work to further its cause thereby contributing to the vulnerable milieu in which the LTTE's free functioning in India as a lawful association, if allowed, would be highly detrimental to the sovereignty and territorial integrity of India;

And whereas the LTTE continues to be an extremely potent, most lethal and well-organized terrorist force in Sri Lanka and has strong connections in Tamil Nadu and certain pockets of southern India. The LTTE continues to use the State of Tamil Nadu as the base for carrying out smuggling of essential items like petrol and diesel, besides drugs to Sri Lanka;

And whereas the LTTE will continue to remain a strong terrorist movement and stimulate the secessionist sentiment to enhance the support base of the LTTE in Tamil Nadu as long as Sri Lanka continues to remain in a state of ethnic strife torn by the demand for Tamil Eelam which finds a strong echo in Tamil Nadu due to the linguistic, cultural, ethnic and historical affinity between the Sri Lankan, Tamils and the Indian Tamils in Sri Lanka;

And whereas for the reasons aforesaid, the Central Government is of the opinion that the LTTE is an unlawful association and there is a continuing strong need to control all such separatist activities by all possible means;

And whereas the Central Government has the information that—

- (i) enquiries on the activities of the LTTE cadres, dropouts, sympathizers who have been traced out recently in the State of Tamil Nadu would suggest that the cadres sent to Tamil Nadu would ultimately be utilized by the LTTE for unlawful activities;
- (ii) the activities of pro-LTTE organizations and individuals have come to notice in India, despite the ban in force and attempts have been made by these forces to extend their support to the LTTE;
- (iii) the LTTE leaders have been cynical of India's policy on their organization and reaction of the State machinery in curbing their activities;

And whereas the Central Government is of the opinion that the aforesaid activities of the LTTE continue to pose a threat to, and are detrimental to, the sovereignty and territorial integrity of India as also public order and, therefore, should be declared as an unlawful association;

And whereas the Central Government is further of the opinion that because (i) of its continued violent and disruptive activities prejudicial to the integrity and sovereignty of India; (ii) it continues to adopt a strong anti-India posture and also continues to pose a grave threat to the security of Indian nationals, it is necessary to declare the LTTE as "an Unlawful association" with immediate effect;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and proviso to sub-section (3) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Liberation Tigers of Tamil Eelam (the LTTE) as an unlawful association and directs that this notification shall, subject to any order that may be made under Section 4 of the said Act, have effect on and from the date its publication in the Official Gazette.

[F No. I-11034/1/2006-IS.III]

L. C. GOYAL, Jt. Secy.